

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2741

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
20 अग्रहायण, 1946 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना

2741. श्रीमती साजदा अहमद:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हेतु विनियमक वातावरण में सुधार लाने के लिए किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार देश भर, विशेषकर पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए उभर रहे अवसरों का आकलन करती है अथवा आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उन विदेशी निवेशकों अथवा कंपनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है अथवा प्रवेश करने का विचार है;
- (घ) सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) इन निवेशों और सुधारों के माध्यम से रोजगार सृजन की अनुमानित संभावनाएं क्या हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

- (क) से (ङ.): इलेक्ट्रॉनिकी वेल्यू चेन के क्षेत्र में बड़े निवेशकों को आकर्षित करने और प्रोत्साहित करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं और रणनीतियां तैयार की गई हैं:
- (i) इलेक्ट्रॉनिकी के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: अब तक इस पीएलआई योजना के तहत 9,349 करोड़ रुपये का वृद्धिशील निवेश किया गया है। इससे 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन हुआ है।
 - (ii) आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना: इस पीएलआई योजना के तहत अब तक 501 करोड़ रुपये का वृद्धिशील निवेश किया गया है। इससे 10,245 करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन हुआ है।
 - (iii) सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परियोजना के साथ सेमीकॉनडक्टर कार्यक्रम को मंजूरी दी है। उक्त कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित चार योजनाएं शुरू की गई हैं:

क. 'भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की स्थापना के लिए संशोधित योजना'- इस योजना के अंतर्गत भारत में सिलिकॉन सीएमओएस आधारित सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की स्थापना के लिए पारि-पास्सु के आधार पर परियोजना लागत की 50% राशिकी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

ख. 'भारतमेंडिस्प्लेफैबकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना'
भारतमेंडिस्प्लेफैबकीस्थापनाकेलिएपरियोजनालागतकी राशिकीवित्तीयसहायताप्रदानकी गई है। 50%

ग. 'भारतमेंकम्पाउंडसेमीकंडक्टर/सिलिकॉनफोटोनिक्स/सेंसरफैब/डिस्क्रीटसेमीकंडक्टरफैबऔरसेमीकंडक्टरअसेंबली, टेस्टिंग, मार्किंगऔरपैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटीसुविधाओंकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना'-
भारतमेंकम्पाउंडसेमीकंडक्टर/सिलिकॉनफोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएससहित) फैब/डिस्क्रीटसेमीकंडक्टरफैबऔरसेमीकंडक्टरएटीएमपी/ओएसएटीसुविधाओंकी स्थापनाकेलिएपारि-पास्सु के आधार पर पूंजीगतव्ययकी 50% राशिकीराजकोषीयसहायताप्रदानकी गई है।

घ. 'डिजाइनलिंकडप्रोत्साहन(डीएलआई) योजना'-डिजाइनअवसंरचनासहायताकेअलावा, इसयोजना मेंप्रतिआवेदन 15 करोड़ रुपयेकीअधिकतम सीमा के अधीनव्यय पात्रता की50 % तक "उत्पादडिजाइनलिंकडप्रोत्साहन राशि" और 5 वर्षोंकेशुद्धबिक्रीटर्नओवरकी6 % से 4 % तक की "डिप्लायमेंटलिंकडप्रोत्साहन राशि" प्रदानकी गई है लेकिन यह राशि 30 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सरकारनेमोहालीस्थितसेमीकंडक्टरप्रयोगशालाकेआधुनिकीकरणकोभीमंजूरीदेदीहै। इसकेअलावा, सेमीकंडक्टरपारिस्थितिकीतंत्रकेविकासमेंसहयोगकेलिएसिंगापुर, अमेरिका, यूरोपीयसंघऔरजापानकेसाथसमझौताज्ञापनपरहस्ताक्षरकिएगएहैं।

अप्लाइडमैटीरियल्सद्वारा 4 वर्षोंमें 400 मिलियनडॉलरकेनिवेशकेसाथबेंगलुरुमेंएकसहयोगीइंजीनियरिंगकेंद्रस्थापितकिया गयाहै। यहइंजीनियरिंगकेंद्रसेमीकंडक्टरविनिर्माणउपकरणोंकेलिएप्रौद्योगिकियोंकेविकासऔरव्यावसायीकरण परकेंद्रितहै। एएमडीनेबेंगलुरुमेंअपनासबसेबड़ावैश्विकडिजाइनकेंद्र, एएमडीटेक्नोस्टारस्थापितकियाहै। यहकेंद्र 3डीस्टैकिंग, आर्टिफिशियलइंटेलिजेंसऔरमशीनलर्निंगसहितसेमीकंडक्टरप्रौद्योगिकीकेडिजाइनऔरविकासपरकेंद्रित है।

भारतएकमजबूतसेमीकंडक्टरईकोसिस्टमबनानेकीदिशामेंआगेबढ़रहाहै। सेमीकंडक्टरइंडियाकार्यक्रमकेतहत 1,48,746 करोड़रुपयेकेसंचयीनिवेशवाली 4 सेमीकंडक्टरइकाइयोंकोमंजूरीदीगईहै। इनइकाइयोंपरनिर्माणकार्यतेजीसेचलरहाहै।

डिजाइनलिंकडइंसेटिवस्कीमकेतहत 15 सेमीकंडक्टरडिजाइनकंपनियोंकोसहायतादीजारहीहै। इसकेअतिरिक्त, 41 सेमीकंडक्टरडिजाइनकंपनियोंकोसी-डैकबेंगलुरुमेंचिपिनसेंटरमेंस्थापितराष्ट्रीयईडीएटूलग्रिडद्वाराउपलब्धकराएगईडीएउपकरणोंतकपहुंच केलिएमंजूरीदीगईहै।

इनपहलोंकेपरिणामस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिकीकाघरेलूउत्पादनवित्तवर्ष 2019-20 में 5,33,550 करोड़रुपयेसेबढ़करवित्तवर्ष 2023-24 में 9,52,200 करोड़रुपयेहोगयाहै, जिससेलगभग 16% कीचक्रवृद्धिवाषिकदर से ('सीएजीआर') वृद्धि हुईहै। उद्योगकेअनुमानकेअनुसार, इलेक्ट्रॉनिकीक्षेत्रमेंलगभग 25 लाखरोजगार (प्रत्यक्षऔरअप्रत्यक्ष) पैदा हुएहैं।

अप्रैल 2019 से अब तक भारत को इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र की 356 कंपनियों से लगभग 3,290 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 28 हजार करोड़ रुपये) का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में प्राप्त वर्षवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
2019-20	422.37
2020-21	375.31
2021-22	416.99
2022-23	539.96
2023-24	695.75
2024-25 (Q2 तक)	839.57
कुल	3289.94
<i>स्रोत: एफडीआईसेल, डीपीआईआईटी</i>	

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में अवसर अखिल भारतीय स्तर पर होते हैं। कई राज्यों ने इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पर अपनी स्वयं की नीतियां विकसित की हैं, जो इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय नीतियों की पूरक हैं। इसलिए, पश्चिम बंगाल सहित कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने राज्य में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के अवसर का लाभ उठा सकता है।

देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से संबंधित नियामक परिवेश में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) प्रमाणन के क्षेत्र में व्यापक रूप से लचीलापन लाने के लिए अनिवार्य पंजीकरण आदेश:

यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सुरक्षित मानकों के अनुरूप हों, सरकार ने बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन विनियमन, 2018 की योजना-11 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021 की अनुसूची के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अधिसूचित किया है। विवरण एमई आईटीवाई की वेबसाइट (<http://meity.gov.in/esdm/standards>) पर उपलब्ध है।

(ii) चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी): सेलुलर मोबाइल हैंडसेट, कलाई में पहनने योग्य उपकरण (जिन्हें आमतौर पर स्मार्ट घड़ियों के रूप में जाना जाता है) और श्रवण योग्य उपकरण तथा उन के उप-संयोजनों/इनपुटों/भागों/उप-भागों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए पीएमपी को अधिसूचित किया गया है।

(iii) खरीद प्राप्ति आदेश (पीपीओ): इस सार्वजनिक खरीद आदेश के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दी गयी है, ताकि स्थानीय मूल्य संवर्धन में उत्तरोत्तर वृद्धि करके घरेलू उद्योग की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके, जिससे आत्मनिर्भरता के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

(iv) सीएचआईएमपोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण को बंद करने के लिए आयात नीति में संशोधन:

डीजीएफटी ने अधिसूचना 41/2024-25 दिनांक 29.11.2024 के माध्यम से आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 85 के अंतर्गत आने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स के आयात के लिए आईटीसीएचएस कोड 85423100, 85423900, 85423200, 85429000 और 85423300 के लिए चिप आयात निगरानी प्रणाली

(सीएचआईएम) केतहत अनिवार्यपंजीकरणकोबंदकरदियाहै।
इससेइलेक्ट्रॉनिकीऔरसेमीकंडक्टरपारिस्थितिकीतंत्रकेलिएव्यापारकरनेमेंआसानीबढ़ेगी।

- (v) **100% प्रत्यक्षविदेशीनिवेश (एफडीआई) :** मौजूदाएफडीआईनीतिकेअनुसार, इलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माण (भारतकेसाथभूमिसीमासाझाकरनेवालेदेशोंकोछोड़कर) केलिएआटोमैटिक रूटकेतहत 100% तकएफडीआईकीअनुमतिहै, जोलागूकानूनों/नियमों; सुरक्षाऔरअन्यशर्तोंकेअधीनहै। भूमिसीमासाझाकरनेवालेदेशोंकोएफडीआईकीमंजूरीप्रेसनोट 3 (पीएन 3) अधिसूचनाकेमाध्यमसेदीजारहीहै।
- (vi) **पीएलआईक्षेत्रकेलिएवीज़ाजारीकरनेकीप्रक्रियाकोसरलबनाना:**
सरकारनेइलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणकेलिएपीएलआईअनुमोदितकंपनियोंसेपीएलआईक्षेत्रकेअंतर्गत आनेवालीकिसीभीकंपनीकेलिएपीएलआईव्यवसायवीज़ाजारीकरनेकीप्रक्रियाकोसंशोधितऔरवि स्तारितकियाहै। इसकेअलावा, पीएलआईव्यवसायवीज़ाकेलिएआवेदनकरनेकीप्रक्रियाकोपूरीतरहसेऑनलाइनकरदियागयाहै।
- (vii) **इलेक्ट्रॉनिकीवैल्यू चेनऔरएमओडब्लूआरइकाइयोंमेंरियायतीदर (आईजीसीआर) परमालकेआयातपरस्पष्टीकरण: सीबीआईसीनेपरिपत्रसंख्या 26/2024-सीमा शुल्कदिनांक 21.11.2024 केमाध्यमसेस्पष्टकिया हैकिमध्यस्थ वस्तुनिर्माताद्वाराआयातकेएजारहेसामानजोकिसेलुलरमोबाइलफोनकेअंतिमनिर्माताकोकुछवि निर्माण/मूल्यसंवर्धनकेबादआगेकीआपूर्तिकेलिए एमओडब्लूआरइकाइहैं, आईजीसीआरनियम, 2022 केतहतशुल्ककीरियायतीदरकेलाभकेलिएविधिवतपात्रहैं, लेकिन इसके लिएअन्यसभीशर्तेंपूरीहोनी चाहिए। इसकेअलावा, यहभीस्पष्टकियागयाहैकिएमओडब्लूआरइकाइअबआईजीसीआरछूटकेसाथ-साथशुल्कस्थगनकालाभउठासकतीहै, बशर्तेकि उसके द्वाराआईजीसीआरनियमोंऔरएमओडब्लूआरप्रावधानोंमेंनिर्धारितशर्तोंकाअनुपालनकिया गया हो।**
- (viii) **सेक्शन 65 इकाईसेदूसरेगोदाम/सेक्शन 65 इकाईमेंमालकीआवाजाहीपरस्पष्टीकरण:**
सीबीआईसीनेनिर्देशसंख्या 16/2024- सीमाशुल्कदिनांक 25.06.2024 केतहतस्पष्टकियाहैकिसेक्शन 65 इकाईसेदूसरेगोदाम/सेक्शन65 इकाईमेंपरिणामीमालकेहस्तांतरणकीअनुमतिएमओडब्लूआरकेतहतनिर्धारितशर्तोंकेअनुपालन केअधीनहै।
- (ix) **श्रव्यऔरपहननेवालीवस्तुओंकेविनिर्माणमें सहायताकेलिएसंशोधन:**
सीबीआईसीनेअधिसूचनासंख्या 33/2023-सीमा शुल्कदिनांक 27.04.2023 केतहतश्रव्यऔरपहननेवालीवस्तुओंकीपीएमपीअधिसूचनामेंसंशोधनकिया, जिसमेंकहागयाकिसीमाशुल्कअधिनियम, 1975 कीपहलीअनुसूचीकीव्याख्याकेसामान्यनियमोंकेनियम 2 (क) काप्रावधानघटकों/इनपुट/भागों/उप-भागोंकेआयातपरलागूनहींहोगा, भलेहीऐसेसामानएकसाथप्रस्तुतकिएजाएं।
- (x) **टैरिफसंरचनाको युक्तिसंगत बनाना:**
इलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकेघरेलूविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकेलिएटैरिफसंरचनाकोयुक्तिसंगतबनायागया है, जिसमेंअन्यबातोंकेसाथ-साथसेलुलरमोबाइलफोन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिकघटक, टीवीकेलिएसेटटॉपबॉक्स, एलईडीउत्पादऔरमेडिकलइलेक्ट्रॉनिकीउपकरणशामिलहैं।

- (xi) **पूँजीगतवस्तुओंपरमूलसीमाशुल्कसेछूट:**
निर्दिष्टइलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकेविनिर्माणकेलिएअधिसूचितपूँजीगतवस्तुओंको "शून्य"
मूलसीमाशुल्कपरआयातकीअनुमतिहै।
- (xii) **प्रयुक्तसंयंत्रऔरमशीनरीकासरलीकृतआयात:**
इलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणउद्योगद्वाराउपयोगकेलिएकमसेकम 5
वर्षोंकेअवशेषजीवनवालेप्रयुक्तसंयंत्रऔरमशीनरीकेआयातकोखतरनाकऔरअन्यअपशिष्ट
(प्रबंधनऔरसीमापारआवागमन) नियम, 2016
मेंवनऔरजलवायुपरिवर्तनमंत्रालयकीअधिसूचना,दिनांक 11.06.2018
केअनुसारसंशोधनकेमाध्यमसेसरलबनायागया है।
